कड़ी मेहनत और लगन से किए कार्यों से मिली सफलता का फल मीठा होता है।
– अज्ञात

देश की संप्रभुता

टिकटॉक न देखना या कोई और चीनी ऐप इस्तेमाल न करना भारत में किसी के लिए भी जीवन–मृत्यु का सवाल नहीं है। लेकिन भारत जैसे विशाल बाजार से हाथ धो बैठना संबंधित चीनी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

ज्योति शाह।

सरकार ने टिक टॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला आधिकारिक तौर पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है, फिर भी दुनिया जानती है कि यह चीन के खिलाफ की गई एक ठोस जवाबी कार्रवाई है। दो हफ्ते पहले सीमा पर हुई हिंसक झड़प में बीस जवानों की शहादत के बाद भारत सरकार चीन के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने का दबाव महसूस कर रही थी।

कूटनीतिक मोर्चे पर तत्काल किसी बड़े कदम की गुंजाइश नहीं है और सैन्य कार्रवाई जितनी टाली जा सके उतना अच्छा। ऐसे में मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करके जहां देश में जनमत के उबाल को ठंडा करने की कोशिश की गई है, वहीं चीन को यह संदेश भी दे दिया गया है कि दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ना उसके लिए खासा नुकसानदेह हो सकता है।

लद्दाख के चर्चित आविष्कारक सोनम वांग्चुक के सुझावों के अनुरूप ही ऐप्स पर बैन लगाने का यह फैसला देशवासियों के जीवन या उनकी जरूरतों के किसी अनिवार्य पक्ष से नहीं जुड़ा है। टिकटॉक न देखना या कोई और चीनी ऐप इस्तेमाल न करना भारत में किसी के लिए भी जीवन–मृत्यु का सवाल नहीं है। लेकिन भारत जैसे विशाल बाजार से हाथ धो बैठना संबंधित चीनी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दिक्कत इसके साथ सिर्फ एक है कि युद्ध की तरह व्यापार में भी घटनाओं की गति को नियंत्रित करना एक तो क्या, दोनों पक्षों के बूते से बाहर होता है। कितने भी सोच–विचार के बाद फैसला करें, पर यह आपके हाथ में नहीं होता कि अगला उस पर कैसे रिएक्ट करेगा।

गलवान घाटी की घटना के बाद भारत सरकार की तरफ से यह पहला ही फैसला है जिसे उसकी ठोस प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। इसके बावजूद बाजार में हर तरह के चीनी माल की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। चीनी उत्पादों के बहिष्कार की अपीलों के बीच इन चीजों का कारोबार करने वाले लोग दबाव में हैं। दोनों तरफ बंदरगाहों पर माल पड़ा है जिसे उठाया नहीं जा रहा है। इनमें से ज्यादातर का भुगतान भी हो चुका है। उनके बर्बाद होने या अनबिका रह जाने का सीधा नुकसान भारतीय कारोबारियों के सिर आएगा। अभी हफ्ता–दस दिन पहले सरकार द्वारा इंडस्ट्री से यह जानकारी मांगने की खबर आई थी कि चीन से आने वाले माल पर हमारी किस क्षेत्र में कैसी और कितनी निर्भरता है। यह जवाब रातोंरात तो नहीं मिलने वाला।

पिछले दस–पंद्रह वर्षों से चीन लगातार हमारा एक या दो नंबर का बिजनेस पार्टनर है। वहां से आने वाले बहुतेरे मध्यवर्ती सामान हमारे कई उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में टिकने लायक बनाते हैं। हमें देखना होगा कि अभी की क्रिया–प्रतिक्रिया इन उद्योगों के लिए घातक न सिद्ध हो। कोविड–19 और लॉकडाउन ने पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन से व्यापारिक टकराव हमारे उद्योग जगत के लिए तीसरा धक्का न साबित हो।

एक साथ रहना

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

बौद्ध भिक्षु शन्द ओएक स्रोत की रचना करते हैं। ष्सभी संवेदनशील प्राणी के साथ पवित्र भूमि में एक साथ जन्म लेंष्दृइस प्रकार मूल भावना से सीमित अर्थ निकालें जो केवल शुद्ध प्राणियों की बात करते हैं। 1920 के दशक में, एक जापानी बौद्ध भिक्षु, शीओ बेंक्यो, जो बौद्ध धर्म के स्कूल से संबंध रखते थे, उन्होंने पहली बार सामाजिक संदर्भ में क्योसे शब्द का प्रयोग अन्योन्या श्रय के विचार को निरूपित करने के लिए किया। उन्होंने आश्रित उत्पत्ति की अवधारणा को एक साथ रहने की अवधारणा से संयुक्त किया। उन्होंने पवित्र भूमि में जन्म लेने की इच्छा के स्त्रोत की "एक साथ रहने (सभी संवेदनशील प्राणी के साथ) की अवधारणा से पुनर्व्याख्या की। सह–अस्तित्व से तात्पर्य यह है कि कुछ बिंदुओं पर टकराव की संभावना से इंकार किए बिना एक साथ रहना।

संपादकीय

सीमांत समुदायों तक पहुंच

इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में यह भी देखना होगा कि किस प्रकार हमारी जनतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया अपने संवाद और संदेशों से राज्य के व्यापक गरीब–गुरबा और सीमांत पर बसे समुदायों को जोड़ पाती है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार से बड़ी संख्या के प्रवासी बड़े शहरों में रोजी–रोजगार के लिए जाते हैं। इस कोरोना काल में उनमें से ज्यादातर अत्यंत दुख झेलते हुए बिहार लौट आए हैं। ये लौटे हुए प्रवासी बिहार के गांवों में फैले हुए हैं। ये अपने कुल–कुटुंब, गांव और राज्य की आर्थिक जीवन शक्ति के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। उनमें से ज्यादातर अब बेरोजगार हैं। हलांकि बिहार सरकार इनकी जीविका को पुनर्नियोजित करने की कोशिश में लगी है किंतु बिहार के पब्लिक ओपिनियन में उनका मुद्दा महत्वपूर्ण होकर उभरा है। ऐसे में बेरोजगारी के साथ प्रवासियों के गृह प्रदेश में उनके रोजगार का प्रश्न चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरेगा। सत्ता पक्ष इनकी घर वापसी, इनके रोजगार के लिए किए गए अपने प्रयासों को गिनाएगा तो विपक्ष की आलोचना प्रवासियों की परेशानियों और सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाए जाने में हुए विलंब पर केंद्रित होगी।

सरकारी दलों के डिजिटल घोषणापत्र इन्हीं मुद्दों के आस–पास केंद्रित होंगे। गरीब कल्याण योजना और वायरस से उत्पीड़ित जनता को आर्थिक मदद तो इन घोषणापत्रों के पन्नों में दर्ज होगी ही। इस चुनाव में यह भी देखना होगा कि हमारे राजनीतिक दल किस प्रकार की रचनात्मक कार्ययोजना के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के एक महान योद्धा के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं।

सवाल है कि इन चुनावों की शक्ल–सूरत कैसी होगी? वादों और चुनावी घोषणाओं में कैसा परिवर्तन लाएगा कोरोना? महामारी के दिनों में चुनाव भारतीय समाज और जनतंत्र दोनों के लिए निस्संदेह एक नया अनुभव होगा।

पुरानी प्रचार शैली

बद्रीनारायण।

बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जो भारतीय जनतंत्र की तकदीर रचता है। लेकिन यह पहला राज्य है जहां कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल है कि इन चुनावों की शक्ल–सूरत कैसी होगी? वादों और चुनावी घोषणाओं में कैसा परिवर्तन लाएगा कोरोना? चुनाव प्रचार कैसा होगा? महामारी के दिनों में चुनाव भारतीय समाज और जनतंत्र दोनों के लिए निस्संदेह एक नया अनुभव होगा। इन चुनावों में राजनीतिक संवाद के लोकप्रिय रूप, जैसे मिलना–जुलना, रैली, प्रदर्शन आदि शायद सामान्य रूप में देखने को न मिले। मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुने हुए कार्यकर्त्ताओं की बहुत सीमित संख्या की मीटिंग जरूर देखने को मिल सकती है। नेता और कार्यकर्त्ता डोर–टु–डोर कैंपेन कर वोट मांगते भी दिख सकते हैं और छोटी–छोटी साइकिल रैलियां भी नजर आ सकती हैं।

90 के पहले की ही तरह टैक्सी–टेंपो पर भोंपू लगा कार्यकर्ता अपने–अपने पार्टी के चुनाव चिह्नों पर मुहर लगाकर विजयी बनाने की अपील करते भी शायद हमें दिख जाएं। घर में बैठे, दलानों पर सुस्ताते और खेतों में काम करते लोगों के कानों में गूंजती ये आवाजें ही उन्हें इस

बार लोकतंत्र के संदेशों से जोड़ेंगी। फ्लैक्स के होर्डिंग, बैनरों में भी कोई दिक्कत नहीं है। दीवारों पर उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिह्नों के पोस्टर जो चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद हाल के दशकों में कम हो गए थे, संभव है इस बार लौट आएं। रैलियों में इस बार खर्च कम होंगे। जो धन रैलियों में खर्च होने से बचेगा, वह पार्टियां और उम्मीदवार प्रचार के अन्य साधनों को विकसित करने में लगा सकते हैं।

इस बार के चुनावों में, खासकर गांवों में 70–80 के दशक में उपयुक्त होने वाले छोटे पर्चे और चुनावी पैंफलेट्स भी चुनाव प्रचार के माध्यम के रूप में लौट सकते हैं। एक बात तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रचार काफी कुछ वर्चुअल मोड में होगा। ऑनलाइन जनसंवाद रैलियां होनी शुरू ही हो गई हैं। फेसबुक लाइव, गूगल मीटिंग, ऑनलाइन चौट से पार्टियां और उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंटों को जोड़े रखेंगी। हर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता का अपना ऑनलाइन ग्रुप होगा, जिससे ऑनलाइन संवाद के जरिए वह अपने प्रभार क्षेत्र को मॉनीटर कर पाएगा।

इस चुनाव में स्मार्ट फोन का चलन बढ़ेगा। बहुत संभव है कि नेता और पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन और स्थानीय चुनाव कार्यालयों को लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि से हाइटेक बनाकर रखें। वाट्सऐप ग्रुप, एसएमएस तो प्रचार के माध्यम बने ही रहेंगे। टिकटॉक, वीचौट तथा अन्य चाइनीज ऐप्स बंद होने के कारण ऑनलाइन प्रचार की रचनात्मकता में शायद थोड़ी कमी आए परंतु गैर चीनी ऐप्स के माध्यम से ऐसे प्रयास चलते रहेंगे। बिहार के इस चुनाव में रैलियां और साक्षात प्रचार न के बराबर होने के कारण अखबारों के साथ–साथ टीवी चौनलों की भी भूमिका बढ़ जाएगी। बड़े नेता इस बार प्रायरू ऑनलाइन माध्यमों से और टीवी चौनलों के जरिए ही लोगों तक पहुंचेंगे। रेडियो और कम्यूनिटी रेडियो का भी महत्व इस चुनाव में बढ़ सकता है। जाहिर है, ऑनलाइन प्रचार का वे राजनीतिक दल ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, जिनके संगठित और व्यवस्थित कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर फैले हुए हैं। ऐसे दल अपने समर्थकों को ज्यादा व्यवस्थित ढंग से ऑनलाइन संवादों से जोड़कर उन्हें निचले तलों और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे।

अष्टयोग- 5100

2	3		4		6	7
	30	6	34	2	31	3
5	1	7		6	2	
6	30		33		34	5
	5	2		7	1	6
7	35	4	35		28	
4	7		6		2	1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5099 का हल

4	7	5	6	3	2	1
1	31	2	38	6	28	3
5	1	6	3	7	2	4
6	36	3	33	1	28	5
3	5	7	4	2	1	6
7	32	4	31	4	33	2
2	3	1	4	5	6	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

कई घरेलू खेल खेल सकते हैं

मोहन। सत्ता पक्ष इस क्षेत्र में अपने कार्यों को गिनाकर अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा तो विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर सरकार की असफलता को सामने लाने के जतन करेगा। इस महामारी के काल में राजनीतिक दल जनता को राहत देने के लिए दिखाई गई अपनी सक्रियता और की गई अपनी सेवा को राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार बिहार विधानसभा के इस चुनाव में सेवा की राजनीति भी एक मुद्दा होगी। जहां तक सवाल चुनावी मुद्दों और दलों व प्रत्याशियों में लगने वाले आरोप–प्रत्यारोप का है तो इसकी बानगी अभी से दिखने लगी है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चुनावी विमर्श बिजली, पानी, सड़क और विकास की जगह कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों, स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े सवालों, जन स्वास्थ्य के अन्य मुद्दों और टेस्ट किट, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता आदि के इर्द–गिर्द केंद्रित होगी।